



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, १३ जुलाई, १९९२/२२ आषाढ़, १९१४

हिमाचल प्रदेश सरकार

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-२, ६ जुलाई, १९९२

संख्या ई० एक्स० एन० एफ०-११-३५/७४-III.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, प्रथम नवम्बर, १९६६ से तुरन्त पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्रों को यथा लागू और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, १९६६ की धारा ५ के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब आबकारी अधिनियम, १९१४ (१९१४ का १) की धारा ५६ द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य गभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस वर्ष ५ विकास द्वारा स्थापना दिवस समारोह जो जुलाई, १९९२ को मनाया जाएगा के लिए ५ विकास, मार्फत ५६ ए०पी०ओ० के पक्ष में १००० वोटलें रम, २०० वोटलें विस्की/ब्रान्डी और १०० वोटलें बीयर पर से आबकारी शुल्क व निर्धारित शुल्क के आधे पर जो मुबलिंग १४,९१२.५० रुपये बनती ह पर छूट प्रदान करते हैं ।

आदेश द्वारा,

ए० एन० विद्यार्थी,
वित्तियुक्त एवं सचिव ।

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 6 जुलाई 1992

संख्या पी सी एच-एच ए (5) 19/82.--इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25 जून, 1991 जिसके अन्तर्गत उप निदेशक-II पंचायती राज विभाग मुख्यवास को श्री रण बहादुर सिंह, प्रधान ग्राम पंचायत बसगापुर, विकास खण्ड मशोबरा, द्वारा पंचायत निधि के दुरुपयोग एवं छलहरण करके अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने के मामले में जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था।

क्योंकि उप निदेशक-II पंचायती राज के सेवा निवृत्त होने के फलस्वरूप उपरोक्त आदेशों का आंशिक रूप से अधिलेखन करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उन शक्तियों का प्रयोग करते हुये जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत प्राप्त हैं, उप निदेशक-II पंचायती राज विभाग के स्थान पर उप निदेशक पंचायती राज मुख्यवास, शिमला को उक्त मामले में जांच अधिकारी नियुक्त करते हैं। वह अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को एक मास के भीतर प्रस्तुत करेंगे। जांच में प्रस्तुत-कर्ता अधिकारी पूर्व आदेशानुसार ही रहेंगे।

हस्ताक्षरित/-
उप सचिव।